**फाइल नं0-71-1002(002)/23/2021**

46/2023/I/293407/2023

**प्रेषक,**

**एस0 पी0 सिंह,**
**अनु सचिव**
**उ0प्र0 शासन।**

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

**चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1** **लखनऊ : दिनॉक 25 मार्च, 2023**

**विषयः- वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ के कैम्पस की आंतरिक सड़कों के सुदृढ़ीकरण/सुधार/मरम्मत कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।**

महोदया,

उपर्युक्त विषयक प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ के पत्र संख्या-पीसीपीसी/2022/पीसी/2022/7176, दिनांक 11.11.2022 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ के कैम्पस की आंतरिक सड़कों के सुदृढ़ीकरण/मरम्मत/सुधार कार्य हेतु पी0एफ0ए0डी0 द्वारा आंकलित लागत **रू0 591.95 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति** तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत पूंजीलेखा पक्ष में लेखाशीर्षक-4210-03-105-41-मेडिकल कालेज, मेरठ हेतु मानक मद-24-वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि रू0 1300.00 लाख में से **रू0 100.00 लाख (रू0 एक करोड़ मात्र)** की धनराशि अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

**नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों-**

1- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07 जून, 2022 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- सुसंगत नियमों और प्राविधानों का पालन करते हुए पारदर्शी प्रक्रिया के तहत प्राक्कलन में निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप समयबद्ध रूप से गुणवत्तापूर्ण कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। प्रस्तावित समस्त कार्यो की गुणवत्ता व आडिट की जिम्मेदारी कार्य कराने वाली संस्था प्रमुख एवं कार्यदायी संस्था की होगी।

3- प्रयोजनान्तर्गत समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाये।

4- प्रायोजना प्रस्ताव आगणन का गठन अधीक्षण अभियंता/ , मरेठ वृत्त लोक निर्माण विभाग , मेरठ द्वारा अद्यतन स्वीकृत दर अनुसूची के आधार पर एंव समस्त कार्य MORTH की विशिष्टियों एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा समयसमय पर जारी- विभागीय सरकुलर के अनुरूप कराया जायेगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- प्रयोजना प्रस्ताव में 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि अनुमन्य कर दी गई है। कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रयोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।

6- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं को यथावत् मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्थाप्रधानाचार्य का/ होगा।

7- प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाये।

8- प्रायोजनान्तर्गत प्राविधानों का यथावत मानते हुए किया गया है , जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य केा सम्मिलित करना, कार्यो के आकार में वृद्धि एंव अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

9- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से महानिदेशकप्/रधानाचार्य द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजनाकार्यक्रम के अन्तर्गत न तो/ स्वीकृत है और न वर्तमान एवं भविष्य में किसी अन्य योजनाकार्यक्रम में/ आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

10- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

11- कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों तथा प्रायोजना को निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत पूर्ण किये जाने की जिम्मेदारी महानिदेशक/प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था की होगी।

12- प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाये।

13- कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा।

14- प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/मेडिकल कालेज के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

15- प्रायोजना का निर्माण स्वीकृत लागत में ही पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित कराया जाये।

16- बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य हेतु सेन्टेज अनुमन्य नहीं होगा।

17- अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को डाकघर/बैंक खाते में नही रखा जायेगा।

18- संबंधित परियोजना के आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

19- कार्यदायी संस्था को आवश्यकतानुसार धनराशि अवमुक्त की जायेगी। विभागाध्यक्ष कार्यालय में तैनात वित्त नियंत्रक का यह उत्तरदायित्व होगा कि धनराशि का कोषागार से आहरण आवश्यकता के अनुसार ही किया जाये।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,00,00,000 ( रुपये एक करोड़ मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आयव्ययक मे- अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031054100 मेडिकल कालेज मेरठ मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-3-587/दस-2022-23, दिनांक 19 मार्च, 2023 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

**भवदीय,**

**( एस0 पी0 सिंह )**
अनु सचिव।

**संख्या/तद्यदिनांक, उपरोक्तानुसार।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ।
3. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4. श्री कुलदीप रस्तोगी, संयुक्त सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, मेरठ।
7. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
8. परियोजना प्रबन्धक, लोक निर्माण विभाग, मेरठ।
9. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
11. गार्ड फाइल।

**आज्ञा से,**

**(एस0 पी0 सिंह)**
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।